कृष्णपाल गूजर:टिकट मिलने का जश्न...

पेज एक का शेष

सेवा करने की ? अब किसी और को भी तो सेवा करने का मौका दे देना चाहिये था। गूजर जी ने देश की या क्षेत्र की क्या सेवा की है बीते पांच साल में वह तो कहीं नज़र आती नहीं, हां लूट-खसूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरावली का अवैध खनन हो या यमुना से रेत का, शराब के ठेके हों, चाहे अवैध बसे, गूजर की लूट कमाई के मोटे स्रोत रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के माध्यम से उल्टे-सीधे काम और जायदादों पर अवैध कब्ज़े व निर्माण से इन्होंने अकूत धन-सम्पदा अर्जित की है। इसी लूट-कमाई को बरकरार रखने व आगे बढाने के लिये जरूरी है दोबारा से लूट का यह परमिट हासिल किया जाय। जब अरबों-खरबों कमाने हों तो करोड़ों खर्च करने में क्या घाटा है ?

यूं तो चुनाव परिणाम की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परन्तु बीते पांच वर्ष का ट्रैक रिकार्ड देखने पर ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता जो कृष्णपाल एवं उनकी केन्द्र व राज्य सरकार ने करके दिखाया हो। हां, सड़कों व गलियों पर नारियल तो जरूर खुद इन्होंने व इनके पुत्र देवेन्द्र ने फ़ोड़े हैं। शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बीते करीब 6-7 वर्षों से निर्माणाधीन है। आज तक भी इसके पुलों पर न तो लाइट लगी हैं, न ही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़कों के बीच में ग्रिल लगी हैं, न पैदल पार करने के लिये पुल बने हैं। राजमार्ग पर वाहनों के चढने व उतरने के लिये बने मार्ग भी अधूरे व बेढंगे हैं।

इसके विपरीत ठेकेदार अनिल अम्बानी रोज़ाना एक से डेढ करोड़ बतौर टोल टैक्स की वसूली बीते करीब 8-9 साल से करता आ रहा है। उसकी लूट कमाई बढाने के लिये गदपुरी पर एक और टोल नाका भी बन कर तैयार हो गया है। यही कृष्णपाल 5 वर्ष पूर्व टोल टैक्स को जजिया कर बता चुके हैं।

मंझावली गांव स्थित यमुना पुल की कहानी **'मज़दूर मोर्चा'** के पाठक कई बार पढ चुके हैं। इसका शिलान्यास 15 अगस्त 2014 को नितिन गडकरी व कृष्णपाल ने करते वक्त इसे दो साल में चालू करने का एलान किया था। पूरे पांच साल कृष्णपाल इस पुल के गीत-गाते जरुर रहे परन्तु इसके बन कर चालू होने के अभी कोई आसार नज़र नहीं आते।

रेलवे सेवा में कतई कोई सुधार नहीं हुआ। पहले की तरह ही आज भी दैनिक यात्रियों को शटलों में भूसे की तरह लद कर जाना पड़ता है। उस पर सितम यह कि हर साल महीने-दो महीने के लिये, किसी न किसी बहाने कोई न कोई शटल रद्द कर दिये जाते हैं। चौथी लाइन का व ओल्ड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का काम जहां कांग्रेस छोड़ गयी थी आज भी वहीं खड़ा है।

पूरे हरियाणा में 30 लाख मज़दूरों से इएसआई 3000 करोड़ सालाना से अधिक वसूलती है परन्तु चिकित्सा सेवाओं का बुरा हाल है। सेक्टर 8 का अस्पताल व डिस्पेंसरियां बेहाल हैं। वहां न स्टाफ़ है न साजो-सामान। कृष्णपाल के अपने क्षेत्र के करीब 6-7 लाख लोग भी केन्द्र सरकार की इस ठगी का शिकार बने हुए हैं। जैसे-तैसे रो-पीट कर यहां एक मेडिकल कॉलेज बन गया, परंतु वहां भी स्टाफ़ व उपकरणों की आज भी भारी कमी है। लेकिन कृष्णपाल को इन सब से क्या लेना-देना। वे तो एक ही बात जानते हैं कि सत्ता के माध्यम से जितना लूटा जा सके लूट लिया जाय और फ़िर इसी लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीत लिया जाय। अब देखना यह है कि जनता उनकी इस सोच से कहां तक सहमत होती है।

करनाल आईटीआई छात्र की मौत.....

पेज आठ का शेष

छात्रों का आरोप है कि यहां पर चालक बसों को नहीं रोकते। छात्रों को बसों के पीछे मजूबरन भागना पड़ता है। निकित की मौत भी इसी वजह से हुई है। हम इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए।

पहले भी हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र सागर की करनाल के सेक्टर-14 चौक पर इसी तरह बस की चपेट में आने से मौत हुई थी, जिसमें रोडवेज बस चालक की लापरवाही सामने आई थी। अंकित की मौत मामले में छात्रों ने जब आईटीआई चौक को विरोधस्वरूप जाम किया तो वहां पुलिस वाले उन्हें वहां से खदेड़ने पहुंच गई। गुस्साए छात्रों ने इसका विरोध किया तो और पुलिसवालों पर पत्थर बरसाए।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, उन पर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। पुलिसिया कार्रवाई से बेकाबू छात्रों ने भी पुलिस पर खूब पत्थर बरसाए। मगर पुलिस ने भी इस घटना में लड़कियों को तक नहीं बख्शा। पुलिस की कार्रवाई में कुछ छात्राओं को भी चोट आई है, जिससे तनाव और अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। डर के मारे लोग इधर—उधर भागने लगे, जिस कारण पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा।

बकौल पुलिस हमें जानकारी मिली थी कि 250—300 छात्र आईटीआई के मुख्य गेट पर हैं और जीटी रोड को जाम किया हुआ है, जिसको रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंची। मगर कुछ शरारती छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस कारण भारी संख्या में पुलिसवालों को चोटें आईं। दर्जनों छात्रों को भी पुलिसिया मार में गंभीर चोटें आई हैं।

वहीं आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें दौड़ा—दौड़ाकर पीटा और उन पर हवाई फायरिंग भी की। हमारे अध्यापकों और प्रिंसिपल को भी आईटीआई कैंपस में घुसकर बुरी तरह पीटा। इस मामले में पुलिस ने अब तक 100 से भी ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन में 148,149,341,332,353 व 8 नेशनल हाईवे एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

गौरतलब है कि आईटीआई चौक पर महीनों से सड़क खुदी पड़ी है और मनमाने अतिक्रमण के चलते पार्किंग भी मनमाने तरीक़े से होती है। बसें स्टॉप पर रुकतीं तक नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है। सवाल है कि जब यहां की क़ानून व्यवस्था इतनी लचर है और महीनों से सड़कें खुदी हुई और अतिक्रमण ग्रस्त हों तो बाकी राज्य की कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा।

यहां पर जो हालात बने हुए हैं, वह मौत को दावत देते प्रतीत होते हैं, और कानून व्यवस्था भी जैसे किसी कांड का ही इंतजार कर रही थी।

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ पूर्व आईपीएस वीएन राय कहते हैं, 'जिस इमारत की खिड़कियाँ टूटी छोड़ दी जाएँ, वहाँ बड़ा आपराधिक हादसा होगा ही। खट्टर के करनाल में सड़कें गड्ढों और अतिक्रमण के लिए जानी जाती हैं। छोटे-मोटे हादसे होते ही रहते हैं, अब एक छात्र की जान जाने से तूफ़ान मच गया है। इतने महत्वपूर्ण चौक पर विकास के नाम पर सड़कें महीनों से खुदी पड़ी हैं और मनमाने अतिक्रमण ने सभी सड़क इस्तेमाल कर्ताओं को अस्तव्यस्त रखा हुआ है। वाहन पार्किंग जहाँ तहाँ मनमाने तरीक़े से होती है। बसें भी स्टॉप पर नहीं रुकतीं। ज़ाहिर है ऐसे में सभी को मानो किसी बड़ी त्रासदी की प्रतीक्षा थी। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी हाईवे व्यवस्था की रोज़मर्रा की रूटीन लापरवाही ही इस बड़े कांड के पीछे है।'

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्क़त हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

मोदी शासन में रक्षा सौदे में हुए राफ़ेल घोटाले

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 7-13 अप्रैल 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व साहित्यिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। पत्रकारिता धर्म निभाते हुए 'मज़दूर मोर्चा' ने मोदी शासन के पांच वर्ष के दौरान किये गये कार्यों व नीतियों का निष्पक्ष व बेबाक मूल्यांकन करना शुरू किया है। इसी कड़ी में पिछले अंक 31-6 अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी व मोदी सरकार के भ्रष्टाचार से लड़ने और नियंत्रण पाने व कोई घोटाला न होने के खोखले दावों की पोल खोलते हुये मोदी सरकार के समय में हुए 15 प्रमुख घोटालों को उज़गर किया गया था। स्वयं मोदी जी व मोदी सरकार की विलक्षणता रही है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार व घोटालों के आरोपों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने के बजाए वे आक्रामक रूख अपनाते हुये विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा देते है और सरकारी एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग आदि को अलसेशन कुत्तों की तरह पीछे लगा देते हैं।

मोदी शासन में रक्षा सौदे में हुए राफ़ेल घोटाले पर एस विजयन द्वारा तमिल में लिखी पुस्तक ''राफेल घोटाला जिससे पूरा देश हिल गया'' प्रकाशित होने पर तमिलनाडू की भाजपा नीत एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस) समर्थित एआईएडीएमके सरकार चौकन्नी हो गई और सम्भवत: सरकार के निर्देश पर तमिलनाडू चुनाव आयोग में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देकर इस पुस्तक के विमोचन पर प्रतिबंध लगा दिया और चुनाव आयोग के एक दल ने छापा मारकर पुस्तक की 142 प्रतियों को जब्त कर लिया, जिसकी 'चुनाव आयोग ने लगाई राफेल घोटाले से जुड़ी किताब के प्रकाशन पर रोक, जब्त की 142 प्रतियां' में समीक्षा की गई है। किताब के विमोचन को रोकना बोलने की आजादी के खिलाफ़ है तथा लोकतंत्र और कानून के विरुद्ध है। इस पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मोदी पर बनी फ़िल्म तो रिलीज हो सकती है लेकिन राफ़ेल पर किताब का विमोचन नहीं हो सकता। यह चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड है।

इस कड़े प्रतिरोध के फलस्वरूप चुनाव के मद्देनज़र केंद्रीय चुनाव आयोग सामने आया। चुनाव आयुक्त अशोक लवाशा ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने राफ़ेल पर लिखी तमिल पुस्तक को जब्त करने के लिये किसी को भी अधिकृत नहीं किया है और इस घटना में संलिप्त अधिकारियों को हटा दिया गया है।

लोगों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने व छवि बनाने के लिये प्रधान मंत्री मोदी अपने शासन काल के पांच साल में 18 महीने 25 दिन विदेश यात्रा पर रहे और लगभग 160 योजनाओं का एलान किया जिसके मीडिया में प्रचार-प्रसार पर 43 अरब 43 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किये गये, जिसका 'ये मदारियों का लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री 226 दिन यात्रा करता है-देश के चौकीदार मोदी की यात्रा, प्रचार तंत्र और योजनाओं की घोषणा से जुड़ी रोचक जानकारियां' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है कि चुनाव के समय जो पोलिटिकल फंडिंग हो रही है, उसमें से 46 प्रतिशत फंडिंग के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं कि कहां से आ रही है जिसका 90 प्रतिशत पैसा भाजपा के पास आ रहा है। ये सीधे तौर पर काला धन है जिसके बारे में मोदी सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने को कुचलने के लिये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह अपराध धारा 124-क के अंतर्गत शामिल किया था। 'क्या राजद्रोह हटेगा ?' में धारा 124-क का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सटीक विश्लेषण किया गया है। इस धारा का मोदी शासन के दौरान खुलकर दुरूपयोग किया गया है और मोदीजी की विचारधारा व नीतियों के आलोचक बुद्धिजीवियों पर राजद्रोह के आरोप लगाये गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिये इस असंवैधानिक कानून को समाप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। गौरतलब है कि इस कानून के जन्मदाता इंग्लैंड समेत न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में इस क्रूर धारा को समाप्त कर दिया है फ़िर भी वहां देशद्रोह की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हरियाणा कांग्रेस के विभिन्न नेताओं द्वारा परिवर्तन बस यात्रा फ़रीदाबाद क्षेत्र समेत पूरे हरियाणा में निकाली गई जिसमें काफ़ी भीड़ शामिल हुई। इस संदर्भ में हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों की सम्भावित चुनावी स्थिति की 'कितना परिवर्तन ला पायेगी कांग्रेस की पविर्तन यात्रा-हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रम को भीड़ के हिसाब से काफ़ी सफ़लता मिली है, लेकिन क्या इससे लोकसभा में सीटें भी मिलेंगी ?' में विवेचना की गई है।

आम जनता तथा विभिन्न सरकारी बैंकों से लूटे हुए हज़ारों करोड़ों रुपयों के महाघोटालों के मुख्य आरोपी फ़रीदाबाद के प्रमुख बिल्डर एसआरएस ग्रुप के मुखिया अनिल जिंदल तथा हरियाणा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रधान पवन जिंदल व उसके भाई मदन जिंदल के काले कारनामों में 'मिलीभगत से हुआ एसआरएस के अनिल जिंदल की जमानत का रास्ता साफ़' तथा 'हरियाणा संघ प्रधान पवन जिंदल व उसका भाई मदन भी बड़ा घोटालेबाज़ है' से सत्ता की मिलीभगत से हुए घोटालों का भंडा-फ़ोड़ किया गया है। इन करतूतों से मोदी जी व खट्टर के 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' जुमले की पोल खुल गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की घोषणा की थी और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसके लिये मोदी सरकार ने शौचालय बनाओ अभियान चलाया और शौचालय बनाने के लिये 12000 रुपये प्रति शौचालय मंजूर किए। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन में मोदी सरकार व प्रशासन की लापरवाही तथा अकर्मण्यता के कारण यह अभियान मात्र एक ढोंग बन कर रह गया, जिसकी '12 हज़ार में शौचालय बनता नहीं, और नहीं बनवाने पर राशन रोक देते हैं अधिकारी में चर्चा की गई है।

गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में उनकी सरकार पर विरोधियों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन संघ परिवार व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गुजरात मॉडल की बहुत प्रशंसा की गई। मोदी जी और मोदी सरकार की कार्यशैली, नीतियों व विचारधारा के आलोचक बुद्धिजीवियों को राष्ट्रविरोधी व देशद्रोही करार देकर जेलों में डाला गया और उनमें से कई की हत्या भी कर दी गई। 'नरेन्द्र मोदी शासन: पांच साल-पंद्रह हत्याएं' में मोदी शासन में हुई ऐसी पन्द्रह हत्याओं का रहस्योद्घाटन किया गया है, जिन्होंने देश को तो शर्मिंदा किया ही दुनियां भर के प्रबुद्ध लोगों ने भी इन हत्याओं पर हम सभी पर उंगली उठाई। आश्चर्य है कि बहुचर्चित गुजरात मॉडल पर लगे काले धब्बे के बारे में मोदी सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाई नहीं की गई। वास्तव में इन हत्याओं द्वारा मोदी सरकार की विचारधारा व नीतियों की आलोचकों को कुचलकर देश में फ़ासीवाद स्थापित करने का प्रयास है।

पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखने पर 'पाकिस्तान एक महीने से लाशें गिन रहा है, और विपक्ष सबूत मांग रहा है-नरेन्द्र मोदी -तो फ़िर आपने लव लैटर क्यों लिखा था ?', मोदी जी द्वारा गरीबों को गैस व गैस चूल्हा देने की योजना घोषणा करने तथा भाजपा नेताओं द्वारा किसी ग़रीब के घर रुकने पर 'जिस ग़रीब के घर रुके पात्रा, वहां नहीं था गैस का चूल्हा-एक बार फ़िर ग़रीब के घर रुकने जा रहा हूं-इस बार आपकी किरकिरी नहीं होने दूंगा', मोदी जी के शौचालय बनाओ अभियान पर 'इनके लिये भी एक शौचालय बनवा दो साल भर मुझे तंग करते हैं', मोदी जी के मैं भी चौकीदार अभियान पर 'अरे भाई, इतनी सिक्योरिटी...आगे डाकू है क्या ?-नहीं बीजेपी वाले!' तथा फ़िल्मी अभिनेत्रियों के राजनीति में आने पर 'फ़िल्मों से अब आप राजनीति में आ गई हैं, एक्टिंग में थोड़ा सुधार लाइए...' के जरिये मोदी जी की नीतियों व योजनाओं तथा चुनावी राजनीति पर उचित कटाक्ष किया गया है।